प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

05.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज ऊना के कोटला कलां स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर समिति द्वारा आयोजित वार्षिक धार्मिक महासम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता में कर्म करने का जो संदेश दिया गया है, उसी कर्मयोग की भावना से प्रदेश सरकार जनकल्याण के कार्यों में निरंतर जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, आम लोगों और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशील, समावेशी व मानवीय दृष्टिकोण के साथ योजनाओं को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार निराश्रित बच्चों के लिए माता–पिता की भूमिका निभा रही है। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के 6 हजार निराश्रित बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का कानूनी दर्जा प्रदान किया है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के लिए राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बंद होने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 16वें वित्तायोग के सामने राज्य का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। यही कारण था कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सहित 17 राज्यों को दी जाने वाली आरडीजी बंद कर दी। उन्होंने दावा किया कि 15वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के बारे में स्पष्ट संकेत दिए थे और हिमाचल की सुक्खू सरकार को सत्ता संभालने के बाद इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए थी लेकिन सरकार अंत तक सोई रही। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा कि वह हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का सबसे अमीर राज्य बनाने के अपने विजन का प्रदेश की जनता के सामने खुलासा करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल भाजपा और केंद्र सरकार को दोष देने में बिता दिया है लेकिन अब प्रदेश की जनता काम चाहती है।

इंदु गोस्वामी

राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने कहा है कि केंद्र में वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से वर्ष 2026 के बीच हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों के रूप में 76 हजार 7 सौ 99 करोड़ रूपए प्रदान किए गए। राज्यसभा सांसद ने आज धर्मशाला में कहा कि इसी अवधि में प्रदेश को एक दशमलव 41 लाख करोड़ रूपए ग्रांट इन एड के रूप में दिए गए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2020–21 से वर्ष 2026 के बीच 8 हजार 309 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की जो वित्त आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त है। उन्होंने कहा कि ये राशि 50 सालों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल में शत–प्रतिशत रेललाइनों का विद्युतीकरण किया गया। जबकि यूपीए सरकार में एक भी रेल ट्रैक का विद्युतीकरण नहीं हुआ।

बोर्ड परीक्षा

राज्य में आगामी 3 मार्च से आरंभ होने वाली प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में इस बार करीब एक लाख 84 हजार विद्यार्थी भाग लेंगे। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाला शर्मा ने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं से पहले 20 से 28 फरवरी तक प्रेक्टिकल परीक्षाओं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से 2 हजार 3 सौ 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विशाल शर्मा ने बताया कि नकल रोकने के लिए फलाइंग स्क्वायड बनाए जाएंगे और साथ ही लाईव मॉनिटरिंग सैंटर भी स्थापित किया जाएगा।

उज्जवला योजना

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। प्रदेश के हमीरपुर जिला में उज्जवला योजना 3 प्वाइंट जीरो के तहत अभी तक 5 सौ 23 पात्र लाभार्थियों को रसोई गैस कनैक्शन दिए जा चुके हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता

मतदाता सूची

प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। ये अंतिम प्रकाशन मतदाता सूचियों को लेकर प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद किया गया है।